



सन् 1859 में क्रिसमस के दिन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में पानी के जहाज से 24 जंगली खरगोश पहुँचे। अंग्रेज उपनिवेशी (सेंटलर) थॉमस ऑस्टिन ने इन्हें मंगवाया था, वो अपनी नई ऑस्ट्रेलियन एस्टेट में खरगोश की आबादी बसाना चाहता था। तीन साल में ही वहाँ हजारों खरगोश हो गए। जबकि, ऑस्टिन के अनुसार, सन् 1865 तक अपने एस्टेट में ऑस्टिन 20,000 खरगोशों को मार चुका था। एक नए शोध में पता चला है कि, हालांकि अन्य लोग भी खरगोश लाए थे पर ऑस्ट्रेलिया में इनका मूल स्रोत ऑस्टिन को ही माना जाता है। युनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ता और मुख्य शोध लेखक जोएल एल्वेस ने कहा कि, खरगोश की ऑस्ट्रेलिया में जैविक घुसपैठ निकट रिक्विड इतिहास की सर्वाधिक अद्भुत घुसपैठ है, जिसके पर्यावरण व अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी परिणाम हुए। शोध के लिए वैज्ञानिकों ने यूरोपियन रैबिट्स के, ऑस्ट्रेलिया, टैस्मनिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन से एकत्रित किए गए सैम्पल्स का अध्ययन किया। एल्वेस ने कहा, हमने रैबिट के सभी जींस को सीक्वेंस किया फिर हमने पूरे ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों के कई आनुवंशिक विश्लेषण करवाए और पाया कि अधिकांश खरगोशों में निकट सम्बंध था और उनका विस्तार विक्टोरिया से हुआ था। इससे पता चलता है कि उनका एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर आगमन हुआ था। उन्होंने यह भी पाया कि ऑस्ट्रेलिया के खरगोश वैस्ट इंग्लैंड के खरगोशों से सम्बंधित थे। उन्होंने कहा, “यह बात उस एतिहासिक दस्तावेज से मेल खाती है जिसमें बताया गया है कि सन् 1859 में ऑस्टिन (ऑस्ट्रेलिया) की एक एस्टेट में खरगोशों का आगमन हुआ था। इससे पहले कई बार पालतू खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया लाया गया था पर ऑस्टिन के खरगोश जंगली थे और जंगल के पर्यावरण से उन्होंने बेहतर तरीके से अनुकूलन कर लिया। हमारा मत है कि इसी से उन्हें सफलता मिली।” जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नैशनल अकैडमी ऑफ साइंसेज में छपे शोध नतीजों के अनुसार, घुसपैठिए खरगोशों ने ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। “रैबिट फ्री ऑस्ट्रेलिया” नाम के संगठन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 200 मिलियन खरगोश हैं, जो विविध प्रकार के संसाधनों के लिए स्थानीय प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा करते हैं और पेड़ पौधों को रीजनरट होने से रोकते हैं। इनकी वजह से मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया तेज हो सकती है।

## अमरिन्दर सिंह की पार्टी के भाजपा में विलय को इतना महत्व क्यों दे रही है भाजपा

भाजपा का मानना है, चाहे पिछले चुनाव में कैप्टन साहब की पार्टी को अधिक वोट नहीं मिले थे, पर अमरिन्दर सिंह के आने से अन्य कांग्रेसी नेताओं का भाजपा में आने के लिये रास्ता खुल जायेगा

**-श्रीनंद झा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। जिसकी अपेक्षा थी, वह हो गया है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह भाजपा में शामिल हो गये हैं, उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय भाजपा में कर दिया है। सलही तौर पर देखने से इस घटना को गैर महत्वपूर्ण मानते हुये, अनदेखा किया जा सकता है। अपमानित होने तथा मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद, कैप्टन ने अपनी स्वयं की पार्टी बनाई थी तथा भाजपा एवं अकाली दल (बीडसा) गुट के साथ मिलकर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था लेकिन उनके प्रदर्शन में उल्लेखनीय जैसा कुछ नहीं था। उनकी पार्टी में 28 सीटों पर

- अमरिन्दर सिंह के साथ सुनील जाखड़, राणा गुरमीत सिंह, फतेह सिंह बाजवा भी भाजपा में शामिल हुए हैं।
- कै. अमरिन्दर सिंह की उम्र भी 75 साल से अधिक होने के कारण शायद, उन्हें राजनीतिक पद तो नहीं मिलेगा, पर उन्हें राज्यपाल आदि, संवैधानिक पद देकर संतुष्ट करने का प्रयास होगा, साथ ही उनके परिवार के अन्य सदस्यों, उनकी पत्नी, पुत्री, पुत्र, व पौत्र, जो राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, का राजनीतिक जीवन आगे बढ़ जायेगा।
- भाजपा, अमरिन्दर सिंह के सहयोग से पंजाब में कांग्रेस की जगह लेना चाहती है।

चुनाव लड़ा था तथा 27 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। उनका कुल वोट शेयर 0.5 प्रतिशत तथा 2.3 प्रतिशत रहा था। कैप्टन स्वयं

अपने गढ़ पटियाला में हार गये थे। कैप्टन वृद्ध होते जा रहे हैं तथा भाजपा में 75 वर्ष की अनधिकृत सेवानिवृत्ति के चलते, यह संभव दिखाई नहीं दे रहा कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण राजनैतिक भूमिका मिलेगी। इसके बावजूद, ऐसी कुछ करण है, जिनके चलते भाजपा कैप्टन को अपने लिये महत्वपूर्ण मान रही है। दो बार मुख्यमंत्री रह चुके अमरिन्दर सिंह 2000 में कांग्रेस के पुनरुद्धार का जरिया रहे थे, जबकि 1980 तथा 1990 के दशकों में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के कारण पार्टी की हाल खराब हो चुकी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, कांग्रेस से दिये गये उनके इस्तीफे के कारण, उनकी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## भारत जोड़ो यात्रा

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि “भारत जोड़ो यात्रा”, जिसका नेतृत्व वे कर रहे हैं, का उद्देश्य यह है कि देश का हर वर्ग एवं हर व्यक्ति

- भारत जोड़ो यात्रा को बेहतर कल की दिशा में एक कदम बताते हुए राहुल ने टिवटर पर बताया कि, किस प्रकार आज वे केरल में स्थानीय मधुआरों से मिले व उनकी समस्याओं को जाना।

के साथ एक बेहतर कल की ओर बढ़ने वाले कदमों के बारे में संवाद हो सके। एक फेस बुक पोस्ट में, उन्होंने मधुआरों के साथ सोमवार को हुये संवाद का विवरण दिया तथा कहा कि वे विभिन्न वर्गों से प्रतिदिन इस प्रकार की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## नशे में धुत पंजाब के मु.मंत्री को प्लेन से उतारा

फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर लुफ्थैंसा एयरलाइंस के विमान से उन्हें सुरक्षा नियमों का हवाला देकर उतारा गया

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। निवेशकों को लुभाने के लिए जर्मनी गए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फ्रैंकफर्ट में लुफ्थैंसा एयरलाइंस के विमान से नीचे उतार दिया गया क्योंकि वह इतनी शराब पीए हुए थे कि हंग ले चल भी नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से फ्लाइट में चार घंटे का विलंब हुआ क्योंकि उनका और उनके साथ आए लोगों का सामान फ्लाइट में पहले ही लोड कर दिया गया था, जिसे बाद में निकालना पड़ा। पंजाब सरकार के अधिकारियों ने लुफ्थैंसा क्रू मेम्बर्स को समझाने की कोशिश की कि वे मान को प्लेन से ना उतारें क्योंकि उन्हें अगले दिन के लिए तय कई महत्वपूर्ण मीटिंग्स में भाग लेना है, लेकिन उन्होंने अपनी फ्लाइट के

- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान निवेश आकर्षित करने के लिए जर्मनी के दौरे पर गए थे।
- एक यात्री ने बताया कि, मु.मंत्री मान इतने ज्यादा नशे में थे कि, पत्नी व सुरक्षा स्टाफ के सहारे के बिना खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।
- इस घटना के बाद मान तुरंत दिल्ली लौट आए और सफाई पैश करने के लिए केजरीवाल के घर गए, क्योंकि चर्चा है कि केजरीवाल उन्हें हटा सकते हैं।

सेप्टी रूल्स के साथ समझौता करने से इंकार कर दिया। फ्लाइट में बैठे एक यात्री के अनुसार मुख्यमंत्री मान दारू के नशे में इतने धुत थे कि अपनी पत्नी और सुरक्षा गार्डों के सहारे के बिना खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। लुफ्थैंसा के कर्मचारियों ने उन्हें यह कहकर प्लेन से उतार दिया कि इन्होंने शराब पी ली है और नियमानुसार ये प्लेन में नहीं बैठ सकते। नया मुख्यमंत्री: ऐसी जबर्दस्त अटकलें हैं कि आप संयोजक एवं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने इसे गंभीरता से लिया है, वे मान के स्थान पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## इलैक्टोरल बॉण्ड्स

**-श्रीनंद झा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 18 सितम्बर। विवादस्पद इलैक्टोरल बॉण्ड्स का मुद्दा उठने बस्ते में से फिर बाहर आ गया है क्योंकि इस संबंध में दायर की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के 19

- चुनावी बॉण्ड के विवाद का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में उठा, विवाद यह है कि इससे सरकार को मालूम पड़ जाता है कि बॉण्ड के जरिए राजनैतिक दलों को चंदा कौन दे रहा है।

सितम्बर को सुनवाई करने की संभावना है। इस स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाएं एन.जी.ओ. एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से दायर की गई थीं। राजनीतिक पार्टियों को बैंकिंग चैनल्स के जरिए पारदर्शी फण्डिंग (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## दक्षिण भारत में भाजपा की एन्ट्री को संघर्षमय पर रोचक बनाया तेलंगाना ने

स्मृति इरानी ने जब बहुत हल्ला किया कि, पी.डी.एस. अनाज के पैकेट्स पर प्र.मंत्री का फोटो क्यों नहीं है तो, तेलंगाना सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर पर प्र.मंत्री का फोटो छाप कर गैस की कीमत का पर्चा भी चिपका कर शहर भर में घुमाया

**-लक्ष्मण वेंकट कुची-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। भाजपा दक्षिण भारत को चुनावों के जरिये जीतने के आक्रामक एजेण्डा के साथ वहाँ प्रवेश कर रही है तथा उसने क्षेत्रीय राजनैतिक ताकतों के साथ दिलचस्प जंग का ऐलान कर दिया है तथा क्षेत्रीय ताकतें भी उसके साथ वही रुख इच्छित कर रही हैं। तेलंगाना में यह लड़ाई अब बेहूदा रूप लेती जा रही है। प्रचार, दुष्प्रचार तथा चतुराई के मामले में क्षेत्रीय ताकतें भाजपा का पूरी तरह मुकाबला कर रही

- जब गृह मंत्री हैदराबाद पहुंचे तो, हवाई अड्डे के रास्ते में हजारों पोस्टर लगाये गये “चालीस प्रतिशत” सरकार का आगमन पर स्वागत।
- तेलंगाना सरकार ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक को भी नहीं बखशा। कर्नाटक की भाजपा सरकार पर हर सरकारी निविदा पर चालीस प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप चर्चित है। अतः बंगलौर शहर में ही फ्लैक्स लगे आई.टी. उद्योग को बंगलौर से हैदराबाद शिफ्ट होने के लिये, नारा था “हैदराबाद में चालीस प्रतिशत कमीशन नहीं चलता, अतः यहां आधारभूत ढांचा (सड़कें, पुल, आदि) काम कर रहा है।”

है तथा दौंच-पंच तथा छल-छद्म के मामले में उसे आगे नहीं निकलने दे रहा। जब केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी इस बात पर आग-बबूला हुई कि पी.डी.एस. खाद्यान्नों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर नहीं थी तो टी.आर.एस. ने एल.पी.जी. सिलेंडरों पर, उनकी कीमत के टैग के साथ

प्रधानमंत्री की फोटो भी लगवा दी तथा उन्हें टूट में लादकर सड़कों पर घुमाया तथा इस प्रकार एल.पी.जी. की कीमतों में आये उछाल के मुद्दे को चतुराई के

साथ उठाया तथा इस प्रकार, प्रचार के इस खेल में भाजपा से कम नहीं पड़ी। तेलंगाना में यह लड़ाई अभियंत्रण रूप लेती जा रही है जहाँ, उदाहरणार्थ, पड़ोसी राज्य कर्नाटक के खिलाफ टी.आर.एस. प्रेरित अभियान ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई को भी लपेट में ले लिया है जिससे वे कुद्व हो गये हैं। और अब, एक ताजातरीन तथा चुभता हुआ कटाक्ष, जो अनुमानतः टी.आर.एस. की तरफ से ही आया है, के अन्तर्गत, उस रास्ते के प्रमुख स्थानों पर “40 प्रतिशत सरकार का स्वागत”

के पोस्टर लगा दिये गये हैं, जिस रास्ते से केन्द्रीय गृह मंत्री हवाई अड्डे से शहर तक गये थे। संयत स्वभाव के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने खिन्नता एवं नाराजगी प्रकट करते हुये कहा कि इस प्रकार की हरकतों से दोनों राज्यों के आपसी संबंध बिगड़ेंगे। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि हैदराबाद में ये पोस्टर किसने लगाये थे। लेकिन भाजपा नेताओं का अनुमान है कि यह सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति की ही कारीगरी है जो अपने गढ़ को राष्ट्रीय दल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## बड़ी बैंच का फैसला ही मान्य

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सोमवार को निर्णय दिया कि किसी भी अपेक्षाकृत बड़ी बैंच द्वारा दिया गया फैसला कायम रहेगा, भले ही बहुमत वाले जजों की संख्या कितनी भी हो। उदाहरणार्थ, 7 जजों की बैंच द्वारा

- सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी उलझन दूर कर दी कि, पांच जजों के सर्वसम्मत फैसले पर सात जजों की बैंच का 4:3 से दिया गया फैसला मान्य होगा।

4:3 के बहुमत से दिया गया निर्णय 5 जजों की बैंच द्वारा सर्वसम्मति से दिये गये निर्णय पर प्रभावी रहेगा। संविधान पीठ ने कहा, “अगर 5 जजों की बैंच का निर्णय 7 जजों की बैंच (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## ‘अगर आप इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के तो चुनाव लड़िये’

सोमवार को सोनिया गांधी से मिलने गये शशि थरूर को यह नेक सलाह मिली

**-रेणु मिश्र-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। सोनिया गांधी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को बताया है कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद का आगामी चुनाव नहीं लड़ रहा है।

सूत्र बताते हैं कि स्वयं से आज मिलने आए शशि थरूर से सोनिया ने कहा कि यदि वे इच्छुक हैं तो आगे आएँ और अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। ऐसा माना जा रहा है कि गांधी परिवार इस चुनाव को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष का मुलामा चढ़ाना चाहते हैं और जितने अधिक लोग चुनाव लड़ेंगे यह उतना ही निष्पक्ष प्रतीत होगा। सूत्र कहते हैं कि सोनिया ने यह भी कहा कि चर्चाओं के विपरीत उनका कोई अधिकारिक प्रत्याशी नहीं है।

लेकिन यह खबर पहले ही लीक हो चुकी है कि गांधी परिवार अशोक गहलोत को आधिकारिक उम्मीदवार बनाना चाहता है। चूँकि अब वह इससे इंकार कर रही है तो प्रश्न यह है कि फिर अशोक गहलोत का क्या होगा?

सोनिया गांधी ने पार्टी के केन्द्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिश्री से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने को कहा है। अटकल

- सोनिया गांधी की सलाह से स्पष्ट हो गया कि, गांधी परिवार अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने के बारे में अडिग हैं। साथ ही परिवार यह छवि भी चाहता है कि, “फ्री” व फेयर चुनाव हो। अतः जितने अधिक नेता चुनाव लड़ते हैं, गांधी परिवार के निर्णय में उतनी ही और चमक आ जाती है।

- चर्चा है कि, दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और इस प्रकार गांधी परिवार के चुनाव मैदान से हटने के बाद, कई और अन्य उम्मीदवार भी सामने आ सकते हैं।

- सोनिया गांधी ने इटली से लौटने के बाद अभी तक अशोक गहलोत को बात करने के लिये नहीं बुलाया है।

- अगर गहलोत नामांकन पेपर भरने के पहले इस्तीफा नहीं देते हैं तो, इसे बेअदबी मानेगा गांधी परिवार और अब तक गहलोत को मिला, परिवार का “ब्लाइन्ड समर्थन” वापस लिया जा सकता है।

- पायलट, राहुल की यात्रा में जुड़ने के लिये केरल पहुंचेंगे मंगलवार की सुबह।

यह भी चल रही है कि दिग्विजय सिंह भी इस चुनाव में अपनी ताल ठोक सकते हैं क्योंकि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। मजदर बात यह है कि इटली से

लौटने के बाद सोनिया गांधी ने अब तक अशोक गहलोत से बात नहीं की है। अपनी मां का निधन हो जाने के कारण वे इटली गई थीं। लेकिन खबरें कहती हैं कि 24

सितम्बर को नामांकन भरने की शुरुआत होने से पूर्व वे उनसे बात करेंगी। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। यह महत्वपूर्ण है कि पार्टी के सोनियर नेताओं ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि गहलोत अपना नामांकन भरने से पूर्व या तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें या वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे नामांकन पत्र ना भरें। इसका तात्पर्य यह होगा कि अब तक सोनिया के चहेते रहे व इस पद के लिए पसंद बने अशोक गहलोत के प्रति गांधी परिवार का कोई पक्षपात नहीं होगा।

सचिन पायलट कल सुबह केरल के लिए रवाना हो रहे हैं जहाँ वे वर्तमान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पुनः जुड़ेंगे और इस पद यात्रा में दो दिन और उनके साथ रहेंगे।

इससे उन्हें राजस्थान के परिदृश्य पर राहुल गांधी से बातचीत करने का मौका मिल सकता है और वे यह भी समझ सकेंगे कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ ही मुख्यमंत्री बने रहने के इच्छुक गहलोत की नेटवर्क के प्रति गांधी परिवार का वास्तव में क्या दृष्टिकोण है।

रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुख्यमंत्री पद की कुर्सी ना छोड़ने का गहलोत का रवैया गांधी परिवार को अच्छा नहीं लगा है।